

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(आर.सी.ढेनवाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

37 / 2018
23.03.2018

- 1-रामकेश पुत्र श्योराज जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2-ओमप्रकाश पुत्र श्योराज जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील उनियारा जिला टोंक

-अपीलान्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला-टोंक राजस्थान

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा
दिनांक 16.02.2018. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

- उपरिस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 18.07.2018.

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने आदेश दिनांक 16.02.2018 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नंबर 632 / 11,178,287,257, / 621 कुल किता 4 कुल रकबा 3.83 मे से 2.13 है० किस्म बारानी प्रथम ग्राम विजयगढ पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल अपीलांट्स पर नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना सुने साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट्स का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा दूर्भावना पूर्वक अपीलांट्स के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट्स को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है, जबकि निर्णय में इस तथ्य को कोई हवाला नहीं है। अपीलाण्ट्स ने कब्जा हटाने व भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत

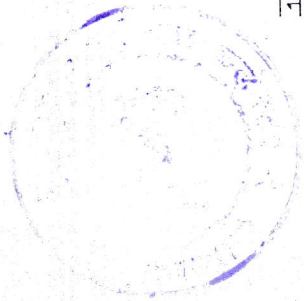
शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

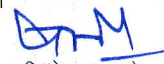
अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्ट्स की विधिवत तामिल हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी राजकीय भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्धीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम विजयगढ के खसरा नम्बर 632/11,178,287,257,/621 कुल किता 4 कुल रकबा 3.83 मे से 2.13 है 0 भूमि पर जोत व चने की फसल काशत कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का के बयान से सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। नायब तहसीलदार बनेठा ने उनके पत्र क्रमांक 79 दिनांक 17.07.2018 से वर्तमान मे अपीलान्ट्स का उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं है की रिपोर्ट प्रेषित की है। अपीलान्ट ने शपथ पत्र पेश किया है कि मेरा उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.02.2018 द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा शास्ती राजकोष मे जमा करादी है तथा अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। नायब तहसीलदार बनेठा यह सुनिश्चित करले की अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर टोंक
टोंक